अमृत वाणी

अक्लमंद काम करने से पहले सोचता है और मूर्ख काम करने के बाद।

– महात्मा गाँधी

उल्टा चोर कोतवाल को डाटें

एक तो गल्ती अपनी, उस पर रौब भी दिखाना। यह कैसे सहन किया जा सकता है लेकिन लगता है आज लोग इसे ही अपना अधिकार समझने लगे है।

मेकॉज के उस डाक्टर के रवैये को ही देखें। एक तो वह मरीज को एक्सपायरी डेट की दवा देता है उस पर जब मरीज उसका विरोध करता है तो उल्टे उसी पर बरस पड़ता है। कितना दुस्साहस! गल्ती मानकर उसे सुधारने की बजाय, दादागिरी। एक तो एक अस्पताल में एक्सपायरी डेट की दवा दिया जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है उस पर अगर उसे कोई चिकित्सक दे तो तब वह दुगुना बड़ा अपराध बन जाता है। चूंकि यह एक जागरुक मरीज का मामला था सो उसने देख लिया। अन्यथा अगर पीड़ित के साथ कुछ अनर्थ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता।

जैसा कि बताया गया है, कान दर्द से बुरी तरह पीड़ित एक मरीज इलाज के लिए मेकॉज पहुंचा था। चिकित्सक ने उसका इलाज कर उसे दवा उपलब्ध कराई मगर जब मरीज व उसके साथियों की नजर दवा की तारीख पर पड़ी तो वो एक्सपायरी डेट की दिखी। इस पर जब चिकित्सक से मरीज ने इसका विरोध किया तो गल्ती मानने की बजाय वे उसके साथ दुर्व्यवहार करने पर उतर आए। ये कैसा न्याय है। एक तो मरीज की अपनी परेशानी, उस पर डाक्टर से सुकून के दो शब्द पाने के बजाय, दुर्व्यवहार।

शासन समय समय पर दवा दुकानों में छापामार कार्रवाई करती है तथा वहां एक्सपायरी डेट की दवा पाए जाने पर उन्हें दंडित किया जाता है। अब अगर सरकारी अस्पतालों में ही एक्सपायरी डेट की दवा दी जाय तो क्या होगा। बस्तर के शासकीय अस्पतालों में ज्यादातार यहां के ग्रामीण अशिक्षित लोग ही इलाज कराते है। एक तो आजकल अधिकांशतः अस्पताल में दवाएं रहती ही नही है। मरीजों को बाहर से खरीदने के लिए कहा जाता है। जो इक्का दुक्का दवाएं मिलती हैं, अगर उनमें भी ऐसी गड़बड़ी हो तो मरीज क्या करेगा।

बस्तर मुख्यालय में चिकित्सा व्यवस्था में परिवर्तन को लेकर इन दिनों वैसे ही लोग काफी असमंजस में है। मेडीकल कालेज शहर से दूर स्थानांतरित हो गया है। संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय महारानी अस्पताल में वीरानी की सी हालात है। अस्पताल का कामकाज पूरी तरह से सामान्य होने में अभी भी कुछ वक्त लगेगा। ऐसे समय में मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार और उन्हें सही दिग्दर्शन दिया जाना बहुत जरुरी है। वैसे भी मेकॉज सह महारानी अस्पताल में समय समय पर मरीजों के साथ कैसा पशुवत आचरण किया जाता रहा है, यह किसी के लिए अन्जान नही है। अच्छा हो, अगर नए सिरे से व्यवस्थित हो रहे मेकॉज और महारानी अस्पताल में उन दुखद स्थितियों की पुनरावृत्ति न हो।

राजकाज

सुप्रीम कोर्ट किससे नाराज

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हालात देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि केजरीवाल सरकार की दशा बिगड़ी हुई है। दरअसल जगह.जगह गंदगी को देख सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई और पूछा है कि आखिर दिल्ली में कचरे के अंबार के लिए ज़िम्मेदार और जवाबदेह कौन है उपराज्यपाल या फ्रि सीएम यह टिप्पणी उस समय शीर्ष अदालत ने की है जबकि केजरीवाल सरकार और उप राज्यपाल के अधिकारों को लेकर एक बड़ा फैसला अदालत दे चुकी हैए लेकिन जंग अब भी जारी है। बहरहाल अदालत ने नाराजगी जताते हुए यह तो जतला दिया कि जो जिम्मेदार हैं वो अपने काम को अंजाम दें न कि आपसी लड़ाई में दिल्ली को नुक्सान पहुंचाएं अब देखिए जिम्मेदारी को कौन निभाता है क्योंकि अधिकार तो सभी मांगते हैं लेकिन कर्तव्यों का पालन कोई नहीं करना चहाता है।

जियो पर सरकार की सफाई

सरकार द्वारा उस जियो इंस्टीट्यूट को उत्कृष्टता का टैग देने की बात कही गई जो अभी तक जमीनी हकीकत में कहीं है ही नहीं। इसे लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरु कियाए जिससे दबाव में आई केंद्र सरकार को सफाई देना पड़ गई। सरकार ने सफाई पेश करते हुए कहा कि उसे उत्कृष्टता का टैग नहीं बल्कि सिर्फ आशय पत्र लेटर ऑफ इन्टेंट दिया गया है। इसके आगे सरकार के नुमाइंदे ने जो कहा उससे यही आभास हुआ है कि कहीं न कहीं सरकार जियो के पक्ष में खड़ी है इसलिए सरकार कह जाती है कि जियो का प्रस्ताव एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तय गाइडलाइन के मुताबिक थाए इसलिए उसे मंजूरी दी गई। बहरहाल इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को निशाने पर ले रखा है जिसे देखते हुए जानकार कह रहे हैं कि इसका असर चुनाव तक बनाए रखने के लिए विपक्ष द्वारा हर संभव प्रयास किए जा सकते हैं। यही देखकर सरकार बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है।

मून का न्यौता अर्थात् मोदी के पुनः प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी

आज देश में जिसे देखिए वही चुनावी चर्चा में कुछ इस तरह रत् है मानों उसे ही तय करना है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। देश में ऐसा माहौल इसलिए देखा जा रहा है, क्योंकि आम चुनाव का समय करीब आता जा रहा है। अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, तो ऐसे में कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री जैसे खेलों को भी प्राथमिकता मिल रही है और सभी इसे लेकर माथापच्ची करने लग गए हैं।

इस राजनीतिक माहौल में जिन्होंने मुद्दों और वादों के आधार पर पिछले आम चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ संसद भेजने का बीड़ा उठाया था, अब वो खामोश नजर आ रहे हैं जबकि विरोधी खेमा मुखर है। इस नकारात्मक सोच को खत्म करने के लिए पार्टी नेतृत्व ही नहीं बल्कि खुद सरकार गंभीर प्रयास करती नजर आ रही है। इन्हीं प्रयासों के चलते ही विदेशों में लगने वाले प्रधानमंत्री मोदी के जयकारे देश में भी खूब सुनाई देते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान दौर पर विदेश से आने वाले प्रमुख नेता मोदी जी को पुनरू प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद देते नजर आ जाते हैं। इस पर यदि यकीन नहीं आता तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे.इन के प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए श्आमंत्रणश् को ही देख लें। दरअसल राष्ट्रपति मून जे.इन चार दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस बीच दोनों देशों के प्रमुखों ने अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए लेकिन जब दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून ने प्रधानमंत्री मोदी को 2020 में उनके देश आने का न्यौता दिया तो सुनने वालों ने इसके अलग.अलग अर्थ निकालने शुरु कर दिए। एक तरफ जहां मोदी समर्थकों ने इसे उनके पुनरू प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी बताया तो वहीं विरोधी पक्ष ने चुटकी लेते हुए कहना शुरु कर दिया कि मून जे नहीं चाहते कि बतौर प्रधानमंत्री मोदी उनके देश में कदम रखेंए संभवतः इसीलिए उन्होंने मौजूदा कार्यकाल में उन्हें देश आने का न्यौता नहीं दिया। अब यदि अगले आम चुनाव में पार्टी व गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं होता है तो क्या बतौर प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण कोरिया की यात्रा कर सकेंगेघ् इस तरह के सवाल लोगों के जेहन में आने लगे हैं। चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत ही शांति और सद्भाव के साथ सरकारें बदल दी जाती हैं, अतः देखना यह होगा कि अगला जनादेश किसे देश की बागडोर सौंपता है और किसे विपक्ष में बैठने का आदेश देता है। आगामी आम चुनाव के परिणाम तय कर देंगे कि मोदी जी मून के आमंत्रण पर यदि दक्षिण कोरिया जाते हैं तो वो किस हैसीयत से जाएंगे। बहरहाल हम तो यही मानकर चल रहे हैं कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे.इन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी है विरोधी खेमा यदि इस भविष्यवाणी को गलत साबित करना चहता है तो उसे भी किसी ऐसे ही प्रमुख विदेशी नेता का सहारा लेना होगा। वैसे तो यह भविष्यवाणी अनजाने में कही गई बात को माध्यम बनाकर निकाली गई है लेकिन कहा तो उन्होंने यही है कि श्वह 2020 में प्रधानमंत्री मोदी की कोरिया यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।श् बकौल मून जे.इन श्मुझे विश्वास है कि हम विभिन्न बहुपक्षीय सम्मेलनों में अपनी घनिष्ठ बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री का यह कार्यकाल आगे भी जारी रहेगा और इस पर आगामी आम चुनाव का विपरीत प्रभाव कतई नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी दोबारा चुने जाएंगे या नहीं इसकी चर्चा अब इसी आधार पर हो रही है। वैसे देखा जाए तो केंद्र सरकार की अधिकांश योजनाओं का कार्यकाल या तो 2020 से 2022 तक का है या फिर इसी कार्यकाल से उनकी अन्य प्रमुख योजनाएं प्रारंभ करने की बात कही जा रही हैए जबकि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल मई 2019 तक का ही है। इसके बाद वो बतौर प्रधानमंत्री दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के साथ विभिन्न बहुपक्षीय सम्मेलनों में बातचीत करेंगे या नहीं और 2020 में कोरिया दौरा करेंगे या नहींए इस पर जनता और पार्टी को ही मोहर लगानी होगी। बहरहाल इन कयासों को नजरअंदाज कर भी दिया जाए तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे.इन ने मोदी सरकार को जीत का मंत्र तो दे ही दिया है। दरअसल मून जे का कहना है कि वो और प्रधानमंत्री मोदी 3पी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इसमें 3 पी का अर्थ लोगों के बीच आपसी सहयोग पीपुल्स समृ प्रॉसपेरिटी और शांति यानी पीस को बढ़ावा देने पर सहमती की बात है। अब यदि इन्हीं 3पी को देश में भी लागू कर दिया जाए तो सरकार के विरोधी भी लाजवाब हो जाएंगे। दरअसल कौन नहीं चाहता कि पीसफुल माहौल में आपसी सहयोग के साथ तरक्की के रास्ते तय किए जाएं। इस पर जरुर मोदी सरकार को विचार करना चाहिए और तमाम कर्ताधर्ताओं को इस लक्ष्य को प्राप्त करने का कड़ाई से पालन करने को कहा जाना चाहिए। चूंकि खुद भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को लेकर राष्ट्रपति मून जे की तारीफकी है अतरू वो इसका महत्व तो जानते ही हैं। इसलिए संभावना यही है कि दोनों देशों के बीच लोगों के ज्यादा मेलजोल को बढ़ावा देने के साथ ही साथ देश में भी तमाम वर्गोंए जातियों धर्मों व संप्रदायों के बीच आपसी मेलजोल वाली समझ को व्यापक करते हुए शांति व्यवस्था बनाने और विकास करने पर ही जोर दिया जाएगा। यदि यह संभव हुआ तो मून जे की भविष्यवाणी फ्लीभूत होने से कोई रोक नहीं पाएगा।

– डॉ हिदायत अहमद खान

(ये लेखक के अपने विचार है)

भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने वोटों की फसल लहलहाने के लिए किसानों की फसलों के समर्थन मूल्य में कथित डेढ़ गुना वृद्धि कर दी किंतु अब यहां अहम् सवाल यह है कि क्या देश का भूखा.प्यासा किसान भाजपाशास्ति केन्द्र सरकार द्वारा उसके सामने फैंकी गई चुनावी रोटी से खुश हो गया है और क्या वह भी इसके बदले में भाजपा के समर्थन वोट के मूल्य में अभिवृद्धि करेगा या भाजपा के प्रति अपनी नाराजी को बरकरार रखेगा खैर अभी तो इस प्रश्न का सवाल भविष्य के कोहरे में दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, किंतु फिलहाल तो यही स्पष्ट हो रहा है कि देश का किसान अपनी अतीत की पीड़ा और अपनों को खोने का गम भुला नहीं पाया है और सरकार की इस चुनावी रोटी में स्वार्थ का नमक ज्यादा महसूस कर रहा है।

क्या किसान भी अपने वोट का समर्थन मूल्य बढ़ाएगा

दमोदी सरकार के इस फैसले को यदि मध्यप्रदेश राजस्थान व छत्तीसगढ़ विधानसभाओं के चुनावों से जोड़कर देखा जाए तो कतई गलत नहीं होगा क्योंकि जिन चैदह फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई हैए वे ही फसलें इन तीनों राज्यों में सर्वाधिक पैदा की जाती हैए राजस्थान से ज्वार जुड़ी हैए तो मूंग महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश से। चूंकि ज्वार की फसल अक्टूबर में ही पकती है और नवम्बर में वह मंड़ियों में आती है और नवम्बर में ही विधानसभा चुनाव हैए इसलिए भाजपा को केन्द्र के इस फैसले का तत्काल राजनीतिक फायदा होने की उम्मीद भाजपा द्वारा की जा रही है। क्योंकि पूरे देश में हर साल 47 लाख टन ज्वार पैदा होती है उसमें से लगभग 36 लाख टन ज्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। इसलिए इस बार सरकार ने इसके समर्थन मूल्य में 780 रूपए की वृद्धि की है। इसी तरह छत्तीसगढ़ को धान का ष्कटौराष् कहा जाता हैए वहां धान के समर्थन मूल्य में दो सौ रूपए की ऐतिहासिक बढ़ौत्तरी की गई है। चूंकि मूंग मध्यप्रदेश की मुख्य फसल है इसलिए उसके समर्थन मूल्य में चैदह सौ रूपए की बढ़ौत्तरी की गईए इस बढ़ौत्तरी का राजनीतिक लाभ महाराष्ट्र में भी भविष्य में किसानों को मिलने वाला है। यूपीएन चुनाव के पूर्व धान के मूल्यों में रू170८. की वृद्धि की थी। भाजपा का मानना है कि उसे इस फैसले का लाभ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में भी मिलेगाए क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने इन तीनों राज्यों की 65 में से 61 सीटे जीती थी। इस तरह कुल मिलाकर 14 मुख्य खरीफफसलों के समर्थन मूल्य में 52 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई।

यद्यपि सरकार के इस फैसले को लेकर कृषि विशेषज्ञों के साथ स्वयं किसान संगठन भी आशंकित हैए वहीं कांग्रेस जैसे प्रतिपक्षी दलों ने भी इसे किसानों के साथ ष्मजाकष् निरूपित किया हैए कांग्रेस का कहना है कि कृषि मूल्य आयोग की ताजा रिपोर्ट को छुपाकर गतवर्ष की रिपोर्ट के आधार पर खरीफफसलों के समर्थन मूल्य में 28 वर्ष पुराने तरीके से यह वृद्धि की गई हैए जबकि कृषि विशेषज्ञों की आशंका है कि यदि ये फैसले लागू होते है तो किसानों की स्थिति में बदलाव जरूर आएगाए बशर्ते कि ये फैसले सिर्फकागजी फैसले ही बनकर न रह जाएघ् वहीं किसान नेता तथा किसान.मजदूर संगठन के संयोजक शिवकुमार शर्मा ष्कक्का जीष् का कहना है कि सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य वृद्धि का ष्लॉलीपॉपष् देकर किसानों को धोखा दिया है। कक्का जी ने कहा कि मंडी एक्ट के तहत समर्थन मूल्य से कम पर अनाज नहीं लिया जा सकताए अतः कम कीमत पर मंडी में अनाज खरीदी पर तुरंत एफ्आईण्आरण् दर्ज होना चाहिएए जहां तक मोदी सरकार का सवाल हैए उसने किसानों को ष्सीण्टूष् पचास फीसदी देने का वादा किया थाए यदि यह दे दिया जाता तो किसानों को खाद.बीजए कीटनाशकए पेट्रोल.डीजलए खेत की लागतए किराया सहित खेती की पूरी लागत पर पचास फीसदी की राहत मिलतीए लेकिन मोदी सरकार ने यह महत्वपूर्ण वादा पूरा नहीं किया और इस वादे को भी जुमले में तब्दील कर दिया।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मोदी जी के ष्सीटूष् सम्बंधी वादे को 2015 तक लागू नहीं करने पर किसानों व अन्य पक्षों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थीए जिसके जवाब में तब केन्द्र सरकार ने शपथ.पत्र के जरिये यह कहा था कि. इसे लागू करना संभव नहीं है और वर्तमान संसाधनों में यह संभव भी नहीं है।

इस तरह कुल मिलाकर देश का किसान यह समझ नहीं पा रहा है कि उसे केन्द्र के इस फैसले को लेकर खुशी क्यों नहीं हैघ् क्या उसे पुराने वादे जो जुमलों में परिवर्तित कर दिए गए उसकी आशंका है या और कुछघ् जो भी होए यह तो सही है कि सरकार ने पन्द्रह हजार करोड़ का यह दांव खेला है और अकेले मध्यप्रदेश में पिछले एक साल में 1321 किसान आत्महत्या कर चुके हैए जबकि महाराष्ट्र तो ष्किसान आत्महत्याष् का गढ़ बन चुका है।

इस प्रकार कुछ मिलाकर मोदी सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले की कई स्तरों समीक्षा का दौर जारी है और यही स्थिति किसान कर्जमाफी के शगूफें को लेकर भी हैए सबसे बड़ा सवाल फ्रि भी यह हवा में तैर रहा है कि देश का आम किसान वोटर इस फैसले से भाजपा के प्रति अपने समर्थन वोट का मूल्य बढ़ाएगा या नहीं।

– ओमप्रकाश मेहता

(ये लेखक के अपने विचार है)

अरविन्द केजरीवाल.... ठंडा ठंडा खाएं

संसार में न कोई किसी का मित्र होता हैं और न किसी का शत्रु। मेरे द्वारा किये गए कर्म ही मेरे मित्र हैं और शत्रु यदि आप किसी की ओर एक अंगुली उठाते हो तो तीन अंगुली आपकी ओर होती हैं। हमने 15 अगस्त को स्वतंत्रता जरूर प्राप्त की हैं उसके बावजूद हम अभी भी पराधीन हैं। कोई किसी के तो कोई किसी के ण्कोई पत्नी के एतो कोई अफसर के ण्कोई मालिक के तो मालिक अपने बड़े सेठ के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के और सरकार राष्ट्रपति के प्रधान मंत्री बहुमत के और पार्टी अध्यक्ष के और इसके ऊपर आपको भगवान् और अपने किये गए कर्मों का फ्ल तो भोगना होगा। कोई धन से दुखी कोई पद से दुखी और कोई परिवार से दुखी। पद हैं तो उसका सुख नहीं अधिकार का सुख और न मिलने का दुःख। ये सब क्या हैं इस पर विचार करना होगा। कोई को सब कुछ नसीब नहीं होता।

अरविन्द केजरीवाल अपनी आदतों स्वाभाव प्रकृति से दुखी हैं। वे चाहते हैं जैसे मोदी जी के पास अलादीन का चिराग हैं वैसे उनके पास भी होना चाहिए। आजकल तो कोई भी क्षेत्र हो चाहे विज्ञानं तकनिकी स्वास्थ्य अर्थ शास्त्र राजनीती शास्त्र इतिहास यानी हर मर्ज़ का इलाज़ मोदी के पास हैं। रोज नित नए विषयों पर भाषण सीख ध्ज्ञान देते हैं चाहे वह अपूर्ण हो या गलत हो क्या करे मोदी जी को बोलने का शौक हैं जिसे हमारे यहाँ बीमारी कहते हैं। जी हाँ बकने की बीमारी। इसी प्रकार केजरीवाल को एक बीमारी हैं की हथेली में राई तत्काल पैदा हो। अरे बाबा बच्चे पैदा करने के लिए शादी करना अनिवार्य हैं पर शादी के बाद बच्चा पैदा हो या न हो ये हमारे हाथ में नहीं पता नहीं उनके यहाँ गरम गरम खाने जरूर मिला होगा पर शादी के बाद तो ठंडा ही मिलता होगा। केजरीवाल को उतावली का रोग हैं और जल्दी ज्वलनशील द्रव्य जैसे भड़कने लगते हैं। भाई जी आप पराधीन हैं आप अधीनस्थों केए आप उपराज्यपाल के उपराज्यपाल केंद्र के या राष्ट्रपति केऔर राष्ट्रपति प्रधान मंत्री के आप जनता के यानि सब दया के पात्र हैं। सब दूसरे को धौंस दिखाते हैं। और केजरीवाल कीआदत चट मंगनी पट ब्याह जैसी हैं।

अरे बाबा सुप्रीम कोर्ट का निरयण आ जाने के बाद कुछ धीरज रखते एतेल और तेल की धार देखते ण्आपस में उपराज्यपाल और आप और आपका काबीना मिलते और पहले एक दूसरे के भावों का आदर देना सीखो। अनेकांतवाद का उपयोग करो। ही शब्द युध्य विवाद कराता हैं और भी शब्द में हल ध्निरयण की संभावना बनी रहती हैं। इसी जगह बात बिगड़ जाती हैं। केजरीवाल सेए पहले से वैसे ही प्रशासनिक अधिकारी उनके विरोधी हैं और आपने न्यायालय के निरयण के तत्काल बाद उनके स्थानांतरण करने का प्रयास किया या किया तो उन्होंने आपके आदेश को नहीं माना तब आपको कैसा लगा यदि आप उस निरयण के बाद शांति से कुछ दिन बैठकर क्रिया प्रतिक्रिया देखते समझते और आप सौहार्द्रता से केंद्र सरकार को विश्वास में लेते और उपराज्यपाल को भी सम्मान देते तो शायद यह मार्ग सुगम होता।

एक बार एक रेलवे का गुमटी मैन अपने घर गया। उसकी पत्नी ने पूछा आपका काम क्या हैं घ्क्या करते हो घ् तो गुमटी मैन बोला मेरे पास बहुत पावर हैं मैं अच्छे अच्छों की गाड़ी खड़ी कर सकता हूँ ! इस पर उसकी पत्नी बोली की मैं भी इस बार आपके साथ चलूंगी। ड्यूटी पर आने के बाद पत्नी बोली आप अपना पावर को दिखाओ। इस पर गुमटी मैन गया और क्रासिंग के गेट लगा दिए। दोनों तरफबहुत भीड़ बढ़ गयी। एक थानेदार आया और देखा न कोई गाड़ी का समय हैं और न कोई गाड़ी का संकेत हैं। उसने गुमटी वाले से कहा कैसे गेट बंद किया घ्तो वह बोला ये मेरे पावर की बात हैं। इस पर थानेदार ने दो थप्पड़ लगाए और बोला खोलो गेट। इस पर उसने गेट खोला। यह सब उसकी पत्नी देख रही थी। उसने पूछा थानेदार ने थप्पड़ क्यों मारेघ्इस पर गुमटी मैन बोला उसने अपने पावर का उपयोग किया और मेने अपने पावर का। सबने अपने अपने पावर का उपयोग किया।

सरकारी तंत्र में कानून की व्याख्या अपने अपने से ढंग से की जाती हैं और सरकार कोई बनिया की दुकान नहीं हैं या कोई होटल नहीं हैं की आपने आर्डर दिया और वहां पूरा हुआ या आपका घर जहाँ आपकी पत्नी तुरंत आदेश का पालन करती। किसी जगह तोवह भी नहीं होता। ण्सरकारी काम मंथर गति से चलता हैं और जहाँ आपका स्वार्थ होगा उसमे विलम्ब होगा। आप स्वयं चिंतन करे की आप किस गति से काम निपटाते हो। इतिहास की पुनरावृत्ति होती हैं।

आप अवमानना के प्रकरण में जाओ एवहां भी निरयण यह होगा की नियमानुसार अपने अपने पावर का ज्ञान रखते हुए। इसके कारण आपका अमूल्य समय बर्बाद हो चूका और हो रहा हैं और आपका लक्ष्य पूरा न होने पर निराशा ध्हताशाध्असफ्लता मिलेंगी। स्वाभाव को बदलना होगा। शुगर कोटेड क्लोरोक्वीन खाना और खिलाना होगी। तुम्हारे जैसे कितने आये और आकर चले गए।

अभी भी समय हैं जब विरोधी ताकतवर हो तो समय की नज़ाकत समझकर अपना समय शुतुरमुर्ग जैसे निकालो अन्यथा आपका बड़बोलापन आपको ले डूबेगा और आप प्राइवेट लिमिटेड हो जायेंगे। कोई नहीं मिलेगा अगले चुनाव में काम करने और न जनता चाहेगी ऐसे सिरफिरे नेता को।

स्वाभाव बदलकर होशियारी से काम करो
जनतंत्र में कोई किसी का न कोई मालिक होता या नौकर
समय के अनुसार तेल और तेल की धार देखों
बीता समय, बोला शब्द, तीर से निकला बाण
और बहता पानी कभी वापिस नहीं आता
संयोग से पूर्ण बहुमत के बाद भी कुछ नहीं कर पाए
मोदी जी ने कैसी हिकमत से अपना समय निकाला
विकास के नाम पर खूब किया विकास स्व और पर का
अन्यथा नाम आपका इतिहास में रह जाएगा बस ।

– डॉक्टर अरविन्द जैन

(ये लेखक के अपने विचार है)